metric tons of rice, with final landing price per ton inclusive of freight in rupees ;

(b) the present price per ton of Indian rice of similar or near quality ; and

(c) the reasons why we had to purchase rice from Philippines ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE) : (a) The quantity 25,000 metric tons of rice purchased from the Philippines on the 26th September, 1968, consisted of 10,000 metric tons of Philippines White Rice IR-8 variety with 35-40% brokens and 15,000 metric tons of Philippines White Rice with 30-35% brokens. The shipment of the IR-8 variety was to be effected by the 15th October, 1968 and that of the other variety by the 15th November, 1968. The price agreed was $ 163.0 per metric ton C and F FO for the IR-8 variety for shipment by 15.10.68 and $ 158.50 per metric ton C and F FO for the other variety to be shipped by 15th November, 1968.

Since the entire quantity against the IR-8 variety of rice was shipped after the specified date, the price of this variety was, by mutual agreement, reduced by $ 3.00 per metric ton C & F. Thus the cost of this rice, including freight, came to Rs. 1200/- per metric ton.

As regards the Philippine White Rice, some of the supplied quantity was delivered after the target date of 15th November, 1968 and consequently a reduction of $ 3.00 per metric ton in price was secured on that quantity. Thus the average cost of this variety of rice, including freight, came to Rs. 1177.48 per metric ton.

(b) Some quantity of the Philippines rice was classified as fine, some medium and some as coarse. The issue price of these three varieties of rice is Rs. 1100/-, Rs. 1020/- and Rs. 960/- per metric ton, respectively.

(c) Rice was purchased from the Philippines to augment the internal availabilities for meeting the requirements of public distribution in various States.

थानों में टेलीफोन व्यवस्था

1897. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :**
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री बलराज मधोक :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री ओम प्रकाश त्यागी : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कानून और व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से सरकार थानों में टेलीफोन की व्यवस्था आवश्यक समझती है ;

(ख) यदि हां, तो देश के कुल थानों में से कितने थानों में अब तक टेलीफोन व्यवस्था की गई है ; और

(ग) भारत के सभी थानों में कब तक टेलीफोन की व्यवस्था किए जाने की सम्भावना है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) सामान्यतः कानून और व्यवस्था बनाये रखने का विषय राज्य सरकार का है और यह प्रश्न कि देश में पुलिस थानों में टेलीफोन की सुविधा होनी चाहिए, सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा नीति निर्धारण का मामला है । फिर भी पुलिस थानों द्वारा की गई टेलीफोनों की मांग पूर्ति शीघ्रता से की जाती है ।

(ख) देश में वास्तव में कितने पुलिस थानों में टेलीफोन की सुविधा प्राप्त है, के सम्बन्ध में इस समय सूचना उपलब्ध नहीं है चूंकि विभाग द्वारा ऐसे टेलीफोनों का अलग से हिसाब नहीं रखा जाता ।

(ग) उपर्युक्त (क) को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

इलैक्ट्रानिक संचार प्रणाली सम्बन्धी अनुसन्धान

1898. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :**
श्री नारायण स्वरूप :